तदनुसार, अब कुल 5 बोलीदाता अर्थात एल1, एल2, एल3, एल4, एल4 रिवर्स नीलामी में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।

9.4.8. आरएफपी बोली बंधपत्र के साथ-साथ करार कार्य निष्पादन गारंटी को भी निर्दिष्ट करेगा जो बोलीदाताओं को प्रस्तुत करना होगा।

9.4.9. टीएसए में टीएसपी और नोडल एजेंसी (अंतर-राज्यीय परियोजनाओं के मामले में)/टीएसपी और यूटिलिटियों (अंतरा-राज्यीय परियोजनाओं के मामले में) के बीच प्रस्तावित क्षतिपूर्ति व्यवस्था भी प्रदान की जाएगी। यह क्षतिपूर्ति टीएसए की प्रभावी तिथि से टीएसपी और नोडल एजेंसी/यूटिलिटियों दोनों पर लागू होगी।

9.4.10. टीएसए, पारेषण सेवाओं को प्रदान करने में देरी की स्थिति में लागू होने वाले परिसमापन नुकसानों को भी निर्दिष्ट करेगा।

9.4.11. टीएसए, बोलीदाता/टीएसपी द्वारा पूरा किए जाने वाले तकनीकी, प्रचालनात्मक और सुरक्षा मानदंडों को भी निर्दिष्ट करेगा।

9.4.12. टीएसपी को सुसंगत विनियमों के अनुसार उपयुक्त आयोग से पारेषण लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

9.5. बीपीसी उन सभी संभावित बोलीदाताओं के साथ बोली-पूर्व सम्मेलन बुला सकता है, जिन्होंने आरएफपी चरण के लिए दस्तावेज मांगे हैं। यदि बोलीदाता कोई परियोजना विशिष्ट विचलन चाहते हैं और बीपीसी को लगता है कि वे विचलन उचित हैं, तो बीपीसी ऐसे विचलन को स्वीकार करने के तर्क के साथ ऐसे विचलन के लिए सहमत हो सकता है। स्पष्टीकरण/ संशोधित-निविदा दस्तावेज उन सभी को दिया जाएगा जिन्होंने विचलनों और स्पष्टीकरणों के बारे में सूचित करते हुए आरएफपी दस्तावेज मांगा था। जहां भी संशोधित बोली दस्तावेज जारी किए जाते हैं, बीपीसी ऐसे दस्तावेज जारी करने के बाद बोलीदाताओं को बोलियां प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम पंद्रह (15) दिनों का समय उपलब्ध कराएगा।

9.6. बोली प्रस्तुत करना और मूल्यांकन

प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए, अर्हता प्राप्त/योग्य बोलीदाताओं की न्यूनतम संख्या दो होगी।

9.7. बोली खोलने वाली समिति:

9.7.1. अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणालियों के लिए बोलियां केविप्रा के कार्यालय में खोली जाएंगी जिसमें केविप्रा से कम से कम एक सदस्य और बीपीसी का एक सदस्य शामिल होगा। केविप्रा और बीपीसी बोली खुलने के दिन दोनों संगठनों से एक-एक सदस्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अपने संबंधित संगठन से एक-एक वैकल्पिक सदस्य को भी नामित कर सकते हैं।

9.7.2. अंतरा-राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए, एसटीयू/राज्य सरकार अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली जैसी संरचना के साथ या जैसा उचित हो, बोलियों को खोलने के लिए एक समिति का गठन करेगी।

9.8. बोली मूल्यांकन समिति:

9.8.1. अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणालियों के लिए, केविप्रा बोलियों के मूल्यांकन के लिए एक समिति का गठन करेगा जिसमें केविप्रा के कम से कम एक प्रतिनिधि और संबंधित क्षेत्रीय विद्युत समितियों के कम से कम दो प्रतिनिधि और एक स्वतंत्र सदस्य होगा। इसके अलावा, यदि परियोजना अंतर-क्षेत्रीय है, तो प्रत्येक संबंधित आरपीसी से कम से कम एक प्रतिनिधि होना चाहिए। स्वतंत्र सदस्य को वित्तीय मामले/बोली मूल्यांकन में विशेषज्ञता प्राप्त होनी चाहिए।

9.8.2. अंतरा-राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए, एसटीयू/राज्य सरकार अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली जैसी संरचना के साथ, या जो उचित हो, बोलियों के मूल्यांकन के लिए एक समिति का गठन करेगी।

9.9. यह सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी बोलियों की जांच की जाएगी कि प्रस्तुत की गई बोलियां सभी तकनीकी मूल्यांकन मानकों पर बोली दस्तावेजों में निर्धारित न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं। बोली दस्तावेजों में निर्धारित न्यूनतम तकनीकी मानदंडों के सभी घटकों को पूरा करने वाली बोलियों पर ही पारेषण शुल्क बोलियों पर आगे के मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा।

9.10. ऑनलाइन प्रारंभिक कीमत बोलियां, बोली मूल्यांकन समिति की उपस्थिति में बोली खोलने वाली समिति द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएंगी। ई-रिवर्स बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सभी अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं को केवल न्यूनतम प्रारंभिक प्रस्ताव के बारे में सूचित किया जाएगा। ई-रिवर्स बोली प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर सभी अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं को केवल सबसे न्यूनतम चल रही बोली दिखाई देनी चाहिए।

9.11. पारेषण प्रभार बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा यदि इसमें प्रस्तुत करने में बोली दस्तावेजों से कोई विचलन होता है।

9.12. ई-रिवर्स बोली प्रक्रिया के दौरान उद्धृत वार्षिक पारेषण प्रभारों में से प्राप्त न्यूनतम पारेषण प्रभारों पर अवार्ड हेतु विचार किया जाएगा। यदि ई-रिवर्स बोली चरण के दौरान कोई बोली प्राप्त नहीं होती है तो न्यूनतम प्रारंभिक प्रस्ताव को अंतिम प्रस्ताव माना जाएगा।

10. मध्यस्थता करना

10.1. टीएसए या टैरिफ के संबंध में किसी भी विवाद के मामले में, वह विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के तहत उपयुक्त आयोग के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

11. बोली प्रक्रिया के लिए समय सारणी

11.1 एकल चरण बोली प्रक्रिया के लिए सुझाई गई समय-सारणी नीचे दी गई है। खरीदार मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर यहां दर्शाई गई विस्तारित समय-सीमा दे सकता है और ऐसे परिवर्तनों को इन दिशानिर्देशों से विचलन नहीं माना जाएगा।

घटनाक्रम	शून्य तारीख से बीता हुआ समय
बीपीसी के लिए राजपत्र अधिसूचना का प्रकाशन	शून्य तारीख
आरएफपी का प्रकाशन	2 दिन
बोली स्पष्टीकरण, सम्मेलन आदि और आरएफपी का संशोधन	40 दिन
तकनीकी और प्रारंभिक प्रस्ताव प्रस्तुत करना	65 दिन
प्रारंभिक प्रस्ताव के खुलने के बाद ई-रिवर्स बोली	75 दिन
बोलीदाताओं की छंटनी और एलओआई जारी करना	ई-रिवर्स बोली प्रक्रिया की समाप्ति के 8 दिन बाद
करार पर हस्ताक्षर	एलओआई जारी होने के 10 दिन बाद

12. संविदा प्रदान करना और निष्कर्ष

12.1. चयन और बीपीसी से आशय पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) (एलओआई) जारी हो जाने के बाद, बोली दस्तावेज में विहित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार टीएसपी बनने के लिए चयनित बोलीदाता परियोजना के लिए तैयार किए गए एसपीवी के अधिग्रहण के लिए शेयर खरीद करार को निष्पादित करेगा और टीएसए निष्पादित करेगा। इसके अलावा, अंतरराज्यीय परियोजनाओं के मामले में, टीएसपी आयोग द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान करने की तारीख से 15 दिन के भीतर, समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यीय पारेषण शुल्क और हानियों की हिस्सेदारी) विनियम के तहत आवश्यक करार यदि कोई हो, को भी निष्पादित करेगा।

12.2. टीएसपी, एसपीवी के अधिग्रहण के लिए शेयर खरीद करार के निष्पादन की तारीख से पांच (5) कार्य दिवसों के भीतर उपयुक्त आयोग को पारेषण लाइसेंस प्रदान करने के लिए एक आवेदन करेगा।

12.3. बीपीसी सभी बोलियों के मूल्यांकन के अंतिम परिणाम को सार्वजनिक करेगा।

12.4. बोली मूल्यांकन समिति के प्रमाण पत्र सहित अंतिम टीएसए, अधिनियम की धारा 63 के अनुसार ई-रिवर्स बोली प्रक्रिया के दौरान उद्धृत वार्षिक पारेषण शुल्क से प्राप्त टैरिफ को अपनाने के लिए उपयुक्त आयोग को अग्रेषित किया जाएगा।

13. पारेषण सेवा करार का समापन

13.1. पारेषण सेवा करार में निर्दिष्ट किसी भी घटना के घटित होने पर नोडल एजेंसी द्वारा पारेषण सेवा करार को समाप्त किया जा सकता है।

13.2. पारेषण सेवा करार के समाप्त होने पर, नोडल एजेंसी परियोजना की पुन: बोली लगाने के लिए उपाय कर सकती है।

14. निरसन और व्यावृति

14.1. समय-समय पर यथासंशोधित 13 अप्रैल, 2006 को जारी "पारेषण सेवा के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी-बोली दिशानिर्देश" एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

14.2. बशर्ते, तथापि, इस तारीख से पहले हस्ताक्षरित कोई भी करार या की गई कार्रवाई 2006 के उक्त दिशानिर्देशों के ऐसे निरसन से प्रभावित नहीं होगी और इसके तहत निरस्त दिशानिर्देशों द्वारा शासित होती रहेगी।

मृत्युंजय कुमार नारायण, संयुक्त सचिव

RESOLUTION

New Delhi, the 10th August 2021

Tariff based Competitive-bidding Guidelines for Transmission Service

1. **Preamble**

No. 15/1/2017-Trans.— Promotion of competition in the electricity industry in India is one of the key objectives of the Electricity Act, 2003 (the Act). Development of a transmission system is essential both for encouraging competition and for creating electricity markets. These guidelines are aimed at facilitating competition in this sector through wider participation in providing transmission services and tariff determination through a process of tariff based bidding.

Section 61 & 62 of the Act provide for tariff regulation and determination of tariff of generation, transmission, wheeling and retail sale of electricity by the Appropriate Commission. Section 63 of the Act states that –

"Notwithstanding anything contained in section 62, the Appropriate Commission shall adopt the tariff if such tariff has been determined through transparent process of bidding in accordance with the guidelines issued by the Central Government."

Tariff based Competitive Bidding Guidelines for Transmission Service and Guidelines for encouraging competition in development of Transmission Projects have been framed under the above provisions of section 63 of the Act. The specific objectives of these guidelines are as follows:

- Promote competitive procurement of transmission services.
- Encourage private investment in transmission system.
- Facilitate transparency and fairness in procurement processes;
- Facilitate reduction of information asymmetries for various bidders;

- Protect consumer interests by facilitating competitive conditions in procurement of transmission services of electricity;
- Enhance standardization and reduce ambiguity and hence time for materialization of projects;
- Ensure compliance with standards, norms and codes for transmission systems while allowing flexibility in operation to the transmission service providers.

2. Scope of the Guidelines

2.1. These guidelines are being issued under the provisions of Section 63of the Electricity Act, 2003 for procurement of transmission services for transmission of electricity.

2.2. The guidelines shall apply for procurement of transmission services for transmission of electricity through tariff based competitive bidding, through the mechanisms described in this notification and to select the bidder who will acquire SPV for a new interstate / intra state transmission system and to build, own, operate and transfer the specified transmission system elements. Standard Bidding Documents for inter-state transmission projects are developed based on Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter-State Transmission Charges and Losses) Regulations; 2020 whereas Standard Bidding Documents for intra-state transmission projects are developed on the basis of the postage stamp method of tariff computation. In case any state adopts the sharing mechanism as specified under Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter-State Transmission Charges and Losses) Regulations, 2020, they may follow the Standard Bidding Documents for inter-state transmission projects with suitable modifications and approval from the Appropriate Government, for award of intra-state transmission projects. For inter-state transmission projects, the project assets along with substation land with rights, right of way and clearances shall compulsorily be transferred to CTU or its successors or an agency as decided by the Central Government after 35 years from COD of project, i.e expiry of contract period, at zero cost and free from any encumbrance and liability. The transfer shall be completed within 90 days of expiry of the contract period failing which CTU shall be entitled to take over the project assets Suo moto. The CEA and the CTU (both being the planning agencies) in the thirty second year (32th) of COD of project will examine the need of upgradation of the system or renovation and modernization of the existing system depending on technological options and system studies at that time. The project may then be awarded to successor bidder selected through a competitive bidding process for renovation and modernization, if required, and operation and maintenance after 35 years from COD of the project. In case, any cost is incurred by CTU towards examining the need of upgradation or renovation and modernization of the existing system and transfer of assets, the same shall be recovered from successor selected bidder.

2.3. For intra-state transmission projects, the project assets along with substation land with rights, right of way and clearances shall compulsorily be transferred to an agency as decided by the State Government after expiry of contract period of project, at zero cost and free from any encumbrance and liability. The contract period for the intra state transmission projects may be 35 years or any period as fixed by the LTTCs or BPC as per the relevant regulations of the Appropriate Commission. The State Transmission Utility (STU)(being the planning agency), in the year which is three (3) years prior to the expiry of the project, will examine the need of upgradation of the system or renovation and modernization of the existing system depending on technological options and system studies at that time. The project may then be awarded to successor bidder selected through a competitive bidding process for renovation and modernization, if required, and operation and maintenance after contract period of the project. In case, any cost is incurred by STU towards examining the need of upgradation or renovation and modernization of the existing system and transfer of assets, the same may be recovered from successor selected bidder.

2.4. Providing transmission services would include all activities related to survey, detailed project report formulation, arranging finance, project management, obtaining transmission license, obtaining right of way, forest clearance, environment clearance, statutory and other necessary clearances, site identification, land acquisition and payment of compensation, design, engineering, quality control, procurement of equipment, material, construction, erection, testing and

commissioning, maintenance and operation of transmission lines and/or substations and/or switching stations and/or HVDC links including terminal stations and HVDC transmission line. It will be in such a manner that the required transmission services as specified in the bid document are provided from execution of the project up to completion and commissioning and its subsequent maintenance and operation so that the facilities are available as per the target for recovery of full transmission charges as quoted by the selected bidder during the e-reverse bidding and adopted by the Appropriate Commission. For availability of transmission system below the target, subject to para 2.5 below, transmission tariff payable to the TSP will be in accordance with the provisions of Transmission Service Agreement (TSA).

2.5. If the availability of the transmission system is below the norms prescribed in the Transmission Service Agreement (TSA), for six consecutive months, the Nodal Agency may terminate the TSA. If the procurer of transmission service or Nodal Agency is of the opinion that the transmission system is of critical importance, it may carry out or cause to carry the operation and maintenance of transmission system at the risk and cost of TSP as a time gap arrangement and approach the Appropriate Commission for suitable action as per the procedure laid down under the Electricity Act 2003.

3. Bid Process Coordinator (BPC)

3.1. A Bid Process Coordinator, herein after referred to as BPC, would be responsible for conducting the bid process for procurement of required transmission services for each inter-state transmission project to be implemented under tariff-based competitive bidding in accordance with these guidelines.

3.2. For procurement of transmission services, required for any inter-state Transmission Project, the Central Government shall notify the CTU or any Central Government Organization/ Central Public Sector Undertaking or its wholly owned subsidiary (Special Purpose Vehicle) to be the BPC. It will be open for Ministry of Power to review the nomination of BPC at any time.

3.3. For procurement of transmission services required for intra-state transmission, the appropriate State Government may notify the STU or any Organization/State Public Sector Undertaking as the Bid Process Coordinator or may engage the services of the BPC notified by the Central Government.

3.4. For conducting the bid process for procurement of required transmission services for each transmission project, BPC shall charge a professional fee @ 1% of the estimated cost of the project subject to minimum of Rs. 5 Crore and a maximum of Rs. 15 Crore for each project.

3.5. Also, all the expenditure incurred by the BPC in the process of selection of the developer in accordance with the provisions of these guidelines shall be recovered from the developer who is finally identified and assigned the task of developing that project. The amount to be recovered shall be indicated in the RFP document so that bidders can take that amount into consideration in the tariff to be quoted by them. Further, there should not be a variation of more than 5% in the amount indicated in the RFP document and amount to be finally paid at the end of bidding process by selected bidder. Also, in case the bidding process for a transmission scheme is cancelled/ de-notified, the expenditure incurred by BPC on that scheme may be recovered when the scheme is re-bid. In case the scheme is no longer required or given on regulated tariff mechanism, the expenditure incurred by BPC on that scheme may be allocated to upcoming schemes with the permission of Ministry of Power.

4. Preparation for inviting bids

4.1. The BPC shall prepare the bid documents in accordance with these guidelines and obtain approval of the Appropriate Government. Alternatively, the BPC can use the Standard Bidding Documents notified by Ministry of Power. Any material deviation from the Standard Bidding Documents shall be made only with the prior approval of the Appropriate Government. A Bid Document will be said to have material deviation from Standard Bidding Documents, if it proposes